

# अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज : एनएमसी से बचने के लिए डायरेक्टर गौतम गोला ने रचा प्रपंच

फ़रीदाबाद (मजदूर मोर्चा) अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज, छात्रों के निदेशक गौतम गोला नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की दंडात्मक कार्रवाई से बचने और मेडिकल छात्रों से फीस लूटने के लिए झूठी खबर फैला रहे हैं कि जल्द ही यहां आईपीडी और जांच सुविधाएं शुरू होंगी। आईपीडी तो दूर अभी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग ही अधूरी पड़ी है, जांच उपकरण का ऑर्डर तो दे दिया गया है लेकिन उनकी स्थापना के लिए कोई जगह ही तय नहीं है, न ही उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम हैं। आधारभूत सुविधा और संसाधनों के अभाव वाले इस कॉलेज में सौ और नए छात्रों को एडमिशन तो दे दिया गया लेकिन उनके रहने खाने तक का इंतजाम नहीं है, मेडिकल की पढ़ाई तो दूर की बात। गोला दो महीने में अस्पताल में ओपीडी, आईपीडी और जांच शुरू करवाने के दावे इसलिए कर रहे हैं कि यदि यह सुविधा शुरू नहीं की गई तो एनएमसी द्वारा जनवरी तक दी गई समय समाप्त होने के बाद मेडिकल कॉलेज पर ताला लटक सकता है।

एनएमसी ने मई में अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था। यहां टीम को ओपीडी में केवल पांच मरीज मिले थे और आईपीडी खाली था, आईसीयू तो था ही नहीं। टीम को बताया गया कि 74 फ़ैकल्टी मेंबर हैं लेकिन केवल 15 ही काम करते मिले। सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और ट्यूटर भी एक तिहाई ही थे। एनएमसी ने मानक पूर्ण नहीं होने के कारण मेडिकल कॉलेज चलाने की स्वीकृति वापस ले ली थी। छात्रों को पढ़ाने के बजाय धार्मिक आडंबरों में डूबे रहने वाले कॉलेज निदेशक ने आका मनोहर लाल खट्टर का चरण वंदन कर कॉलेज और प्रदेश सरकार की इज्जत बचाने की अपील की थी। खट्टर ने डबल इंजन सरकार का वास्ता देकर मोदी की केंद्र सरकार के जरिए एनएमसी की कार्रवाई टलवा दी थी। तब एनएमसी ने जनवरी 2024 तक सारी सेवाएं दुरुस्त करने का समय दिया था।

महज ढाई महीने ही बचे हैं लेकिन



डायरेक्टर गौतम गोला : आकस्मिक निधि भी खत्म कर डाली

मेडिकल कॉलेज जस का तस है। कॉलेज की बिल्डिंग जर्जर है, मुख्य इमारत में फाल्स सीलिंग जगह जगह उखड़ी फुखड़ी टूटी पड़ी है। संस्थान की बिल्डिंग की मरम्मत आदि का ठेका पीडब्ल्यूडी को दिया गया है लेकिन फंड की कमी के कारण बरसों से काम लटका हुआ है। बिल्डिंग पूर्ण नहीं होने के कारण फायर एनओसी नहीं मिली है, हालात को देखते हुए निकट भविष्य में फायर एनओसी मिलने की उम्मीद भी नहीं है। कॉलेज-अस्पताल में बिजली आपूर्ति भी नहीं है। डीजल कभी चार-पांच दिन में मिलता है तो चंद घंटों के लिए जेनरेटर चलाया जाता है। पर्याप्त बिजली न होने से पानी भी तीन से चार दिन में मिलता है। परिसर में प्लंबिंग का काम भी अधूरा है, जो थोड़ा बहुत पानी आता है उसमें भी अधिकतर लीकेज में बर्बाद हो जाता है। पानी के बिना फ़ैकल्टी और छात्र परेशान रहते हैं। परिसर की लिफ्टें असें से खराब पड़ी हैं और चोर एसी निकाल ले गए। वातानुकूलन नहीं से आग या केमिकल से झुलसे मरीजों को भी बिना इलाज लौटा दिया जाता है।

नए सत्र के लिए सौ छात्रों का एडमिशन तो कर लिया और उनके आठ करोड़ रुपये वसूल लिए लेकिन उनके खाने तक का इंतजाम नहीं है। हॉस्टल में मेस नहीं होने के कारण छात्र और फ़ैकल्टी टिफिन सर्विस के भरोसे हैं। बिल्डिंग की सफाई व्यवस्था ऐसी है कि आए दिन सांप

निकलते रहते हैं, जहरीले कीड़े-मकोड़ों की भी भरमार है। छात्रों के सोने के लिए चारपाई तक नहीं खरीदी गई हैं, उन्हें मरीजों के बेड दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्रों को एनॉटॉमी (शरीर रचना विज्ञान) पढ़ाई जाती है। मानक के अनुसार एनॉटॉमी पढ़ाने के लिए दस छात्रों पर एक मृत मानव शरीर होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज को बीते साल एक मृत मानव शरीर मिला था।

समझा जा सकता है कि कॉलेज के छात्रों को एनॉटॉमी पढ़ाने के लिए शरीर नहीं है, ओपीडी में चंद मरीज ही आते हैं और आईपीडी चल नहीं रही कि छात्र पैथोलॉजी, मेडिसिन आदि विषयों को प्रायोगिक रूप से पढ़ और समझ सकें। ऐसे में छात्र मेडिकल की कैसी पढ़ाई कर रहे होंगे समझा जा सकता है।

निदेशक गौतम गोले के बेहतरीन प्रबंधन का नतीजा है कि जून में करीब 27 करोड़ कीमत की दवाएं एक्सपायर हो गई थीं। लगभग एक टुक दवाएं फिर एक्सपायर होने वाली हैं। सिर्फ करोड़ों रुपये की दवाएं ही उनके कुशल निर्देशन में बर्बाद नहीं हुईं कॉलेज का फंड और बजट भी खत्म हो गया। यहां तक कि आकस्मिक निधि (कंटेजेंसी फंड) भी उन्होंने चंडीगढ़ की परिक्रमा करने और रोजाना नलहड भाग जाने में खर्च कर डाली। बजट नहीं होने से जनवरी तक कॉलेज सुचारू रूप से चल पाएगा असंभव प्रतीत होता है।

गौतम गोला निदेशक होने के कारण कॉलेज के प्रबंधन और खर्च के जिम्मेदार हैं लेकिन वह हैं इतने गैर जिम्मेदार कि कर्मपूजा को छोड़ कर हाल ही में पंद्रह दिन के लिए विश्रयाना की गुप्त साधना करने के लिए अंतर्धान हो गया। उनके नहीं होने से पंद्रह दिन तक कॉलेज के लिए जरूरी खर्च नहीं हो सके क्योंकि खर्च करने का अधिकार उनके ही पास था। खैर, अब वह लौट आए हैं लेकिन बजट में धन नहीं होने के कारण वह भी कोई खर्च नहीं कर पा रहे हैं, यानी कॉलेज-अस्पताल, फ़ैकल्टी, छात्र, स्टाफ सब जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं।

निदेशक गोला ने यह भी दावा किया है कि डायग्नोस्टिक मशीनों का ऑर्डर कर दिया गया है और दो महीने में आईपीडी, ओपीडी मरीजों को जांच की सुविधा मिलने लगेगी। मशीनों का ऑर्डर तो कर दिया लेकिन वो लगाई कहां जाएंगी? लैब तो तैयार है नहीं, अधूरी बनी बिल्डिंग में इन मशीनों को रखने की जगह नहीं है, शीशों के दरवाजे खिड़कियों वाले कमरों में रखे जाने से यह मशीनें चोरी हो सकती हैं। चलो मशीनें लग भी गईं तो चलेंगी कैसे, बिजली है नहीं जेनरेटर सहाह में एक दो दिन कुछ घंटों के लिए चल भी जाए तो उससे कोई भला नहीं होने वाला, इसके लिए चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, फंड की कमी के कारण यह होना भी मुश्किल लग रहा है। अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं के हाल

ये हैं कि यहां मामूली चोट लगने पर मरहम पट्टी करने और एंटी टिटनेस वैक्सिन लगाने तक की सुविधा नहीं है, घायल को बीके अस्पताल भेजा जाता है। कहने को तो यह मेडिकल कॉलेज-अस्पताल है लेकिन यहा गर्भवती की जांच और प्रसव कराने तक की सुविधा नहीं है।

फ़ैकल्टी भले ही न हो लेकिन गोले जी ने पैरामेडिकल तथा चतुर्थ श्रेणी के 350 कर्मचारियों को तैनात कर रखा है, मरीज नहीं होने कारण ये सभी ड्यूटी की औपचारिकता निभाते हैं यानी दिन भर

खाली बैठे रहते हैं।

शबरी माला के भक्त गौतम गोला फर्जी खबरें उड़ा कर सरकार और जनता को तो सुनहरें सपने दिखा सकते हैं लेकिन एनएमसी को चकमा नहीं दे सकते। यदि जनवरी में एनएमसी टीम के सर्वेक्षण से पहले ओपीडी में 500 मरीज और आईपीडी में 360 मरीजों के भर्ती होने के साथ तीस बेड वाले आईसीयू की स्थापना नहीं कर पाए तो एनएमसी की गाज गिरने से खुद को बचा नहीं पाएंगे।

## मंझावली हत्याकांड : आरोपी के इशारे पर निर्दोषों को फंसा रही पुलिस



फ़रीदाबाद (मजदूर मोर्चा)। थाना तिगांव अंतर्गत मंझावली गांव में लाठियों से पीट कर मार डाले गए किसान प्रभुनाथ के हत्यारोपियों को पुलिस न केवल बचा रही है बल्कि उनके इशारे पर गांव के निर्दोष लड़कों को जबरन पकड़ रही है। ये आरोप बृहस्पतिवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे मंझावली गांव के लोगों और पीडित पक्ष ने लगाया। गांव वालों को पुलिस आयुक्त ने निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मंझावली गांव, भाटी फार्म निवासी गुड्डू-प्रभुनाथ दंपति सहित उनके बेटे बेटियों पर एक सितंबर की सुबह बारह-पंद्रह लोगों ने हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल प्रभुनाथ की इलाज के दौरान मौत हो गई थी जबकि गुड्डू, बेटा राजेश सिंह और दो बेटियां शरीर तरह से जख्मी हो गए थे। राजेश सिंह ने गांव के ही पूर्व सरपंच राजेश शर्मा, राकेश शर्मा सहित उनके परिवार के बारह लोगों के खिलाफ हत्या का नामजद केस दर्ज कराया था। पुलिस इस केस में अभी तक तीन नामजद आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई है। सीपी ऑफिस पहुंचे गांव वालों में करणपाल यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस मुख्य आरोपी राजेश शर्मा, राकेश शर्मा और करमबीर शर्मा को नहीं गिरफ्तार कर रही, बल्कि उनके इशारे पर गांव के निर्दोष गरीब युवकों को पकड़ रही है। पुलिस का मौजूदा व्यवहार देखने से लोगों की बात पर यकीन सा होता है। पीडिता ने 29 सितंबर को हुए हमले की जानकारी एसएचओ को दी थी लेकिन न तो वो मौके पर आए और न ही उन्होंने कोई निरोधात्मक कार्रवाई की थी। दरअसल, हमलावरों की योजना किसी को कत्ल करने की नहीं बल्कि इन लोगों के हाथ पैर तोड़ने की थी। इसमें मारपीट जैसी हल्की धाराओं में केस दर्ज होता और मुकदमा चलता रहता लेकिन अधिक चोट लगने से प्रभुनाथ की मौत हो गई। तफ्तीश और कार्रवाई की रफ्तार देखते हुए गांव वालों की बात सही लगती है कि ये हमला तिगांव पुलिस की मिलीभगत से हुआ था।

गांव के राम किशोर ने बताया कि घटना में उनका बेटा रामदत्त नहीं था और न ही एफआईआर में उसका नाम है, बावजूद इसके पुलिस आरोपियों के इशारे पर उनके बेटे को फंसा रही है। गांव की ही गीता ने बताया कि राकेश शर्मा के इशारे पर पुलिस उनके बेटे कल्लू को तलाश रही है, बेटे को हाजिर कराने के लिए पुलिस ने उन्हें दो दिन तक अवैध रूप से बंधक बना कर हिरासत में रखा, इसके बाद बिना लिखापट्टी छोड़ दिया।

दिनेश ने आरोप लगाया कि तिगांव थाने में बारह साल से तैनात एसआई धर्मपाल हत्यारोपियों की खुल कर मदद कर रहा है, इसी कारण आज तक मुख्य आरोपी खुले में घूम रहे हैं और पुलिस से मिलीभगत कर निर्दोषों को फंसा रहे हैं। घटना की चश्मदीद गवाह और पीडिता गुड्डू ने भी पुलिस पर निर्दोषों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों को उन्होंने मारते हुए देखा था उनका ही नाम एफआईआर में दर्ज कराया गया है लेकिन पुलिस उन्हें नहीं पकड़ रही, अगर पुलिस किसी निर्दोष को पकड़ेगी तो वह इसका विरोध करेगी। पुलिस आयुक्त राकेश आर्य ने प्रदर्शनकारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन तो दिया लेकिन एक महिला को दो दिन अवैध रूप से हिरासत में रखने वाले दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी। समझा जा सकता है कि जब पुलिस आयुक्त ही कानून और मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाने वाले मातहतों को कुछ नहीं कह रहे तो फिर पुलिस कितनी ईमानदारी से काम करेगी।

